

सं. ओ. वि./कुरु/39-87/31531.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मारकण्डा वनस्पति मिट्टज लि०, शाहवादा मारकण्डा के श्रमिक श्री सून्वा सिंह मार्फत श्री मधुसूदन शरण कौशिश लठमारन स्ट्रीट, जगाधरी (अम्बाला) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 (44) 84-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सून्वा सिंह की सेवा समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. यमुना नगर/21-87/31537.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इन्जि०, हाईडल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुनानगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चैनल नं० 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भूडकलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री राम कुमार, पुत्र श्री बाबू राम, मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा, महा मन्त्री, इंटक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 (44) 84-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम कुमार की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि. यमुनानगर/24-87/31545.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) चीफ इन्जि०, हाईडल प्रोजेक्ट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, गोविन्दपुरी, यमुनानगर, (3) कार्यकारी अभियन्ता, चैनल नं० 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, भूडकलां, डा० खिजराबाद, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री मित्र पाल, पुत्र श्री हलिदा राम मार्फत डा० सुरेन्द्र कुमार शर्मा महा मन्त्री, इंटक धर्मशाला ब्राह्मण रेलवे रोड, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 (44)-83-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उनसे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री मित्र पाल की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?